



R 5369A/16

RS-301-

कैलाश तनय महाबीर साहू ग्राम मलगो, तह० माडा, जिला सिगरौली म०प्र०

— आवेदक

बनाम

— अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब
तहसीलदार मांडा जिला सिगरौली आदेश दिनांक
13/06/16 प्रकरण क्रमांक 12/अ-6/11-12

संक्षिप्त

आवेदक के परिवार की पुस्तैनी कब्जे व दखल की आराजी क्रमांक पुराना 11/17 रकवा 1.200 हे०, आराजी क्र० 530 /6 रकवा 0.800 हे० स्थित ग्राम मलगो, तह० माडा जिला सिगरौली जिसका नया आराजी ख० नं० 314 रकवा 0.73 ए० 469/2464 रकवा 0.15 हे०, 310 रकवा 0.26 हे०, 307 रकवा 0.12 हे०, 294 रकवा 0.17 हे०, 291 रकवा 0.05 हे०, 298 रकवा 0.40 हे०, 210 रकवा 0.18 हे०, कुल 8 किता जुमला रकवा 2.06 हे० है। आवेदक की इन भूमियों के सम्बन्ध में दिनांक 03/07/95 को जरिये प्रकरण क्रमांक 35 अ/9(4) 94-95 के माध्यम से श्रीमान नायब तहसीलदार प्रखण्ड माडा ने दखल रहित उपबन्ध अधिनियम 1984 के अनुसार आवेदक एवं उसके परिवार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि नहीं थी तब पंचायत की अनुशंशा प्राप्त होने पर आवेदक को आराजी क्र० 11/17 रकवा 1.200 हे० एवं 530/6 रकवा 0.800 कुल दो किता रकवा 2.00 हे० का भूमिस्वामी घोषित किया था तत्कालीन पटवारी को शासकीय अभिलेखों में संसोधन का आदेश पारित किया था तदनुसार आवेदक वतौर भूमिस्वामी शासकीय अभिलेखों में दर्ज हुआ। उसे भूमिस्वामित्व के अधिकार को कायम रखने हेतु ऋणपुस्तिका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई थी। सिगरौली जिले में बंदोबस्त की कार्यवाही में ग्राम मलगों की आवेदक की भूमियों को आवेदक के बजाय म०प्र० शासन दर्ज कर दिया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 31/01/12 को प्रार्थी के द्वारा नायब तहसीलदार महोदय के न्यायालय में अभिलेख दुरुस्तगी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु पटवारी प्रतिवेदन में मौके पर आवेदक के भूमि स्वामित्व के अभिलेखों के ताइद होने पर भी तहसीलदार महोदय ने प्रश्नापद आदेश दिनांक 13/06/16 में यह लिखकर कि आवेदक के आवेदन पत्र की सुनवाई की अधिकारिता

म०प्र० शासन
प्रधानमंत्री आवास योजना
जारा ७२५५५
१२/८/१६
मौके आफ कोर्ट
मान्यवर
मण्डल म०प्र० ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा

M

(42)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5369-IV/16

जिला-सिंगरौली

कैलाश साहू/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
05-8-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा स्वामी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील माड़ा के प्रकरण क्रमांक 12/अ-6/2011-12 एवं में पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	